

प्रेषक,

टीकम सिंह पेंवार
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 03 मार्च जनवरी, 2008

विषय:- वित्तीय वर्ष 2007-08 में गंगा कार्ययोजना के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु धन आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 564/गंगा प्रदूषण दिनांक 11.09.2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में हरिद्वार/ऋषिकेश नगरों में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के रखरखाव हेतु अनु 0 लागत रु० 877.94 लाख के प्राक्कलन पर टी०ए०सी० वित्त के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रु० 701.61 लाख के प्राक्कलन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही वर्ष 2005-06 में इस मद में अवमुक्त धनराशि रु० 615.32 लाख का शासन को उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अनुसार अधिक अवमुक्त (585.80-556.09 29.71 (रु० उन्तीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रु० 701.61 लाख में से कम करते हुए (रु० 701.61-29.71 671.19) रु० 671.19 लाख (रु० छः करोड़ इकहत्तर लाख उन्तीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु संलग्न मदवार विवरणानुसार आपके निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि का व्यय इस हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृत अनुदान की धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल कोषागार देहरादून में प्रस्तुत करके आवश्यकतानुसार ही पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त आहरित किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बिल वाउचर्स की संख्या व दिनांक की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति से व्यय की गई धनराशि का विस्तृत व्यौरा तथा मासिक व त्रैमासिक वित्तीय/भौतिक प्रगति यथासमय शासन को उपलब्ध करायेगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण व्यय विवरण सहित शासन तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को चालू वित्तीय वर्ष की 31.03.2008 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4- स्टाफ एवं अन्य मदों पर व्यय टी०ए०सी० के द्वारा अनुमोदित लागत के अनुसार किया जायेगा। यदि अधिक व्यय सम्भावित हो, जो मानक से अधिक हो तो उसका आंगणन बनाकर दिनांक 31.03.2008 के पूर्व टी०ए०सी० की स्वीकृति के उपरान्त ही किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति अनुमोदित लागत के अनुसार ही व्यय किया जायेगा। स्टाफ पर अनुमोदित लागत से अधिक व्यय अपने संसाधनों से ही

- किया जायेगा और इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी।
- 5- व्यय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित फॉट के अनुसार ही किया जायेगा और यदि अनुरक्षण कार्य नहीं है तो स्टाफ पर व्यय में भी कोई वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी और उसका व्यय अनुमोदित लागत में ही सीमित रखा जायेगा।
- 6- गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव का राज्य सरकार की वचनबद्धता की सीमा तक धनराशि व्यय की जा सकेगी और इसके अभिलेखों का रखरखाव योजनावार अलग-अलग किया जायेगा।
- 7- स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष उ0प्र0 शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ए-2-87(1)दस-97-17 (4)75 दिनांक 27.02.1997 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि सहित सेन्टेज चार्ज कार्यों हेतु ही 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगा। इसे कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर लिया जाय।
- 8- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युअल, फाईनेन्शियल हेण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता है तो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- 9- उक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण एक सप्ताह के भीतर शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।
- 10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.03.2008 तक उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, जो धनराशि दिनांक 31.03.2008 तक अप्रयुक्त रहती है उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।
- 11- आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिए ही अनुमन्य है, कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
- 12- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के सिक्की भी दशा में व्यय अनुमन्य न होगा।
- 13- कार्य स्वीकृत राशि तक ही सीमित रखे। अधिक्य किसी भी दशा में न किया जाय। अधिक्य के लिए निर्माण इकाई स्वयं उत्तरदाई होगा।
- 14- निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर चर्च नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय।
- 15- रखरखाव तथा मशीनों पर व्यय नियमानुसार एवं स्वीकृत नामर्स के आधार पर किया जाय। बिना स्वीकृत नामर्स का व्यय अनुमन्य नहीं होगा।
- 16- उक्त व्यय वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मल निकासी एवं सफाई- आयोजनागत -106-वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण-03-गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव हेतु जल निगम को अनुदान (फेज-1 एवं 11)-00-20-सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग की अशाराकीय सं०-797(क)/XXVII(2)/2008 दिनांक 18 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(टीकम सिंह पेंवार)
संयुक्त सचिव

पृ० सं०-2512/उन्तीस(2)/07-2(93पे०)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/हरिद्वार ।
4. कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उत्तराखण्ड पेयल निगम हरिद्वार ।
6. वित्त अनुभाग-2/नियोजन /राज्य योजना आयोग/बजट सेल ।
7. निजी सचिव, मा० पेयजल मंत्री को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
- ✓ 8. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून ।
- ✓ 9. निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून ।
10. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव